

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या: 723/XXVII(7)/2010
देहरादून, दिनांक: 29 अक्टूबर, 2010

स्पष्टीकरण

विषय:-पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या:421/XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008, संख्या:305/XXVII(7)/2009 दिनांक 08 अक्टूबर, 2009 एवं संख्या: 420/XXVII(7)/2010 दिनांक 18 फरवरी, 2010 के संबंध में स्पष्टीकरण/संशोधन।

विभिन्न राजकीय पेंशनर्स संघों द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राजकीय पेंशनर्स के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है:-

क0 सं0	बिन्दु	टिप्पणी
1	2	3
1	<p>ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनको उनकी पेंशन छठे वेतन आयोग से पूर्व न्यूनतम पेंशन 1275/- से कम निर्धारित होकर प्राप्त हो रही थी, को छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कैसे होगा।</p> <p>वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 421 /XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु संख्या:8 में 1-1-2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रु01275 को पुनरीक्षित कर रु0 3500 किया गया है किन्तु इसमें समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1-1-2006 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी का उल्लेख नहीं किया गया है।</p>	<p>वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:421 xxvii (7)/2008 दिनांक 27-10-2008 के द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्रीय सरकार की भांति दिनांक 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है तथा जिसके प्रस्तर-8 में 1-1-2006 से पूर्व पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रु0 1275 को पुनरीक्षित कर रु0 3500 किया गया है तथापि ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जाएगी, जहां पेंशनभोगी ने, पेंशनभोगियों, पर उसके/ उसकी अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु वांछनीय अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामले में रु03500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी। अतः उचित होगा कि इसी आधार पर जिन पेंशनर्स को 1-1-2006 से पूर्व रु0 1275 से कम पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें भी रु0 3500 पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया जाए। पूर्ण अर्हकारी सेवा पूर्ण न करने पर ही समानुपातिक आधार पर न्यूनतम पेंशन में कमी होगी।</p>

2		<p>शासनादेश संख्या: 305 / xxvii(7)/2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-2 के अनुसार पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जहां समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशन भोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1-1-2006 से लागू संशोधित वेतनमान /वेतन बैण्ड में मूल वेतन तथा ग्रेड पे के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।</p>
3	<p>वित्त विभाग के शासनादेश सं0 305/xxvii(7)/2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-3 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 की तिथि 31 दिसम्बर,2009 से आगे बढ़यी जाए।</p>	<p>वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:305/xxvii(7)/2009 दिनांक 8-10-2009 के प्रस्तर-3 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर्स से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 निर्धारित की गई थी किन्तु कतिपय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स संघों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि अभी भी प्रदेश में अधिकांश ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हैं जिनके द्वारा उक्त तिथि तक उक्त प्रारूप भर कर कोषागार में जमा नहीं किया गया है अथवा संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्षों द्वारा उक्त प्रारूप कोषागारों को प्रारूप नहीं जमा किया गया है फलस्वरूप ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त प्रारूप जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 को दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ा दी जाए।</p>
4	<p>वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / xxvii(7) दिनांक 18-2-2010 में जहाँ-जहाँ पर शासनादेश संख्या:221/xxvii(7)/2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 इंगित किया गया है उसके स्थान पर 08 अक्टूबर, 2008 होगा अथवा 08 अक्टूबर,2009।</p>	<p>वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /xxvii(7) दिनांक 18-2-2010 में कतिपय स्थानों पर शासनादेश संख्या:221/xxvii(7)/2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 त्रुटिवश गलत इंगित होने के कारण इसके स्थान पर "08 अक्टूबर,2009 पढ़ा जाए।"</p>

5	<p>वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /XXVII(7) दिनांक 18-2-2010 के बिन्दु संख्या-2 में 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की अनुमन्यता शासनादेश जारी होने की तिथि के स्थान पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर, जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीख से देय होगी अथवा दिनांक 1-1-2006 से होगी।</p>	<p>इस संबंध में पेंशनर्स संघों द्वारा भारत सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या:38/37 / 08-पीएंड पी.डब्ल्यू(ए) दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु संख्या:4.5 के आधार पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीख से देय किये जाने के संबंध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्तांकित कार्यालय ज्ञाप में उक्त व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से ही लागू है। फलस्वरूप वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420/XXVII(7) दिनांक 18-2-2010 के बिन्दु संख्या-2 में संशोधन का आधार नहीं है।</p>
6	<p>वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या: 420/XXVII(7) दिनांक 18-2-2010 के प्रस्तर-1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1-1-06 से दिनांक 26-10-08 के मध्य 20/10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते परन्तु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे उनको पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी। 33 वर्ष से कम सेवा के कारण अनुपातिक कमी नहीं की जाएगी।</p>	<p>वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या: 420/XXVII(7) दिनांक 18-2-2010 के प्रस्तर-1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होने की व्यवस्था को स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या:506 XXVII(7) दिनांक 26-4-2010 के प्रस्तर-1 में स्पष्ट व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 के स्थान पर दिनांक 1-1-2006 से ही लागू होगी अर्थात् उक्त तिथि के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित औसत वेतन का 50 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया गया है।</p>
7	<p>दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/XXVII(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु 8(1) की सातवीं पंक्ति में अब सात वर्ष के स्थान पर "10 वर्ष पर" अनुमन्य होगी अथवा "10 वर्ष तक"।</p>	<p>दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब सात वर्ष के स्थान पर "10 वर्ष पर" के स्थान पर "10 वर्ष तक" पढ़ा जाए।</p>

2- उक्त कालम-3 में प्रस्तावित व्यवस्था के फलस्वरूप संगत कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3- उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यावन्धन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या : 723 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला बैंक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।